



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261945
CG-DL-E-25032025-261945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947

No. 1357]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

का.आ. 1375(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुखना वन्यजीव अभयारण्य, चंडीगढ़ के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 185(अ) द्वारा, तारीख 18 जनवरी 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 185(अ), तारीख 18 जनवरी 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 185(अ), तारीख 18 जनवरी 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“5. मानीटरी समिति. – केन्द्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| (i) | मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्यजीव प्रबंधक, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ सरकार | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | मुख्य वास्तुकार, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ | - सदस्य, पदेन; |
| (iii) | मुख्य अभियंता, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ | - सदस्य, पदेन; |
| (iv) | मुख्य अभियंता, नगर निगम संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ | - सदस्य, पदेन; |
| (v) | निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ | - सदस्य, पदेन; |
| (vi) | सदस्य सचिव, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति | - सदस्य, पदेन; |
| (vii) | पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा | - सदस्य, पदेन; |
| (viii) | संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा | - सदस्य, पदेन; |
| (ix) | राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य | - सदस्य, पदेन; |
| (x) | उप वन संरक्षक (वन्यजीव), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ - | सदस्य-सचिव, पदेन। |

6. मानीटरी समिति के कृत्य.-(1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन अनुसूची में शामिल और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले गतिविधियों की संवीक्षा करेगी। इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर, और, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह ठीक समझे।”

[फा. सं. 25/9/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा , वैज्ञानिक “जी”

टिप्पणी.—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 18 जनवरी 2017 को विस्तृत का.आ. 185(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

S.O. 1375(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Sukhna Wildlife Sanctuary, Chandigarh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 185(E), dated the 18th January, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 185(E), dated the 18th January, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.185(E), dated the 18th January, 2017, namely :-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.**— The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely: -

- | | | |
|-------|--|------------------------|
| (i) | Chief Conservator of Forest cum Chief Wildlife Warden,
Government of Union territory Chandigarh | —Chairman, ex officio; |
| (ii) | Chief Architect, Union territory, Chandigarh | — Member, ex officio; |
| (iii) | Chief Engineer, Union territory, Chandigarh | — Member, ex officio; |

- (iv) Chief Engineer, Municipal Corporation Union territory, – Member, ex officio;
Chandigarh
- (v) Director, Rural Development and Panchayat, Union territory, – Member, ex officio;
Chandigarh
- (vi) Member-Secretary, Chandigarh Pollution Control Committee – Member, ex officio;
- (vii) One representative of Non-Governmental Organisation working – Member, ex officio;
in the field of environment nominated by the Government of
Union territory of Chandigarh for a period of three years
- (viii) One expert in the area of ecology and environment nominated – Member, ex officio;
by the Government of Union territory of Chandigarh for a
period of three years
- (ix) Member of State Biodiversity Board – Member, ex officio; – Member, ex officio;
- (x) Deputy Conservator of Forest (Wildlife), Union territory, -Member- Secretary, ex officio.
Chandigarh

6. **Functions of Monitoring Committee.**— (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department, representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
 - (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in **Annexure-IV**.
 - (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”

[F. No. 25/9/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 185(E), dated the 18th January, 2017.